उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–09(03/45)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में फिल्म अभिनेता श्री सुरेश ओबेरॉय ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र रावत से उत्तराखण्ड में फिल्मांकन एवं पर्यटन से सम्बंधित संभावनाओं पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्मांकन के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही शांति का वातावरण है। उत्तराखण्ड सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध राज्य है। राज्य में फिल्म निर्माण व शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किया गया है। राज्य को फिल्मों के निर्माण हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में टिहरी, हर्षिल, त्रिजुगी नारायण जैसे अनेक स्थान फिल्मांकन के लिए बेहद अनुकूल हैं।

फिल्म अभिनेता श्री सुरेश ओबेरॉय ने कहा कि उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य वास्तव में फिल्मांकन के लिए अनुकूल है। त्रिजुगी नारायण जहाँ की मान्यता है कि यहाँ शिव–पार्वती का विवाह हुआ था। यह स्थान बेहतर धार्मिक पर्यटन गंतव्य व फिल्मांकन स्थल भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड से उनका विशेष लगाव रहा है। उन्होंने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा फिल्मों के फिल्मांकन के लिए फिल्म जगत को दी जा रही सुविधाओं की पहल को भी सराहनीय बताया।

इस अवसर पर फिल्म अभिनेता श्री विवेक ओबेरॉय भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेसनोट–08(03/44)

मुख्यमंत्री ने कुम्भ क्षेत्र में विद्युत लाईनों को भूमिगत करने की योजनाओं का किया शुभारम्भ।

- योजना की कुल लागत 388.49 करोड़
- 70.11 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का भी किया शिलान्यास व लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को आईपीडीएस योजना के अंतर्गत कुम्भ क्षेत्र में विभिन्न विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने वाली 388.49 करोड़ लागत की योजना का भूमि पूजन कर शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कुम्भ स्मारक मैदान हरिद्वार में 4.99 करोड़ लागत 33/11 के0वी0 उपसंस्थान गैण्डीखाता हेतु 22 किमी की 33 के0वी0 लाईन का भी शिलान्यास किाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपसंस्थान गैण्डीखाता के निर्माण होने से गैण्डीखाता, चिड़ियापुर, लालढांग, मिठी बैरी, पीली पड़ाव क्षेत्र के लगभग 4000 उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी व वोल्टेज में सुधार होगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 70.11 करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। खानपुर, पिरान कलियर, हरिद्वार ग्रामीण, झबरेड़ा, भगवानपुर, रूडकी तथा ज्वालापुर विधानसभा के लिए कुल 56.14 करोड़ की कुल 39 योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 32 लोनिवि, 05 पेयजल व सिंचाई विभाग विभाग की 02 योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा रानीपुर, झबरेडा, हरिद्वार शहर में ग्रा0नि0वि0प्र0, चिकित्सा विभाग, लघु सिंचाई विभाग की 13.97 करोड़ रूपये की योजनाओं का लोकार्पण किया। जिनमें रानीपुर विधानसभा में ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड – हरिद्वार के कार्यालय भवन का निर्माण, झबरेड़ा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता, लघु सिंचाई उपखण्ड रूड़की का भवन निर्माण तथा हरिद्वार शहर विधानसभा में चिकित्सा विभाग द्वारा राजकीय मेला चिकित्सालाय हरिद्वार में लोकनिजी सहभागिता के अन्तर्गत डायलिसिस केन्द्र का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कुम्भ क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत 33 के0वी0की 54 किमी तथा 11 के0वी0 122 किमी की भूमिगत लाईनो, 140.20 किमी की भूमिगत एलटी लाईन, 50 कि0मी0 स्ट्रीट लाईट केबल के साथ ही विभिन्न विद्युत लाईनों को भूमिगत करने से कुम्भ क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण होगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ जनपदवासियों के साथ ही हरिद्वार में वर्ष भर आने वाले श्रद्धालुओं को, कुम्भ एवं कांवड़ व समय–समय पर होने वाले मेलों में विद्युत सुरक्षा मिलेगी। किसी भी प्रकार के मौसम आँधी, तूफान व बरसात में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनी रहेगी।

कार्यक्रम में कैबीनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री आदेश चौहान, श्री सुरेश राठौर, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री नरेश बंसल, पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ0 विनोद आर्य, मेयर श्रीमती अनीता शर्मा, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, एमडी यूपीसीएल श्री बी.सी. मिश्रा आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

- **मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में किया पशुपालन विभाग की 101 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास**
- **प्रदेश में हुआ देश के पहले सेक्स सार्टड सीमन उत्पादन परियोजना एवं प्रयोगशाला का शुभारम्भ**
- **राज्य सरकार देगी पशुपालकों को सेक्स सार्टड सीमन की एक डोज के लिये 400रू. का अनुदान**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को श्यामपुर ऋषिकेश में गोकुल योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित 47.50 करोड़ लागत की देश की पहली सेक्स सार्टड सीमन उत्पादन परियोजना एवं प्रयोगशाला का लोकार्पण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग की 11 अन्य योजनाओं के शिलान्यास सहित कुल 101. 52करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें–भ्रूण प्रत्यारोपण प्रशिक्षण केन्द्र कालसी में हॉस्टल का निर्माण लागत 4.63 करोड़, क्रास ब्रीड हिफर रियरिंग फार्म, पशुलोक ऋषिकेश लागत 10.33 करोड़, सैन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, भ्रूण प्रत्यारोपण, कालसी, देहरादून लागत 15.00 करोड़, राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, डुन्डा, उत्तरकाशी लागत 3.51 करोड़, स्टेट रेफरल सैन्टर, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून लागत 3.07 करोड़, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, थलकुण्डी, उत्तरकाशी लागत 2.58, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् देहरादून में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण लागत 4.28 करोड़, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, खलियान बांगर, रूद्रप्रयाग लागत 2.99 करोड़, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, कोपड़धार, टिहरी गढ़वाल लागत 2.64 करोड़, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पीपलकोटी, चमोली लागत 2.50 करोड़, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकॉठा, चमोली लागत 2.49 करोड़ शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेक्स सार्टड सीमन प्रयोगशाला में तैयार होने वाले स्ट्रा का मूल्य यद्यपि 1150 प्रति स्ट्रा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा रू.450 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के पशुपालकों के व्यापक हित में इसके लिए रू.400 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने की घोषणा की, इस प्रकार प्रदेश के पशुपालकों को 1150 रू0 का स्ट्रा मात्र रू.300 में उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए यू0एस0ए0 की फर्म इगुरान सोर्टिंग टेक्नालाजी एल.एल.पी. अनुबन्धित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समेकित दुग्ध विकास योजना के तहत लाभार्थियों को 100 मोटर बाइक भी प्रदान करने की योजना के तहत प्रतीक स्वरूप बाइक की चाबी प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गो वंशीय पशुओं की संख्या 20.06 लाख तथा महिष वंशीय पशुओं की संख्या 9.80 लाख है। इसमें देशी नश्ल के गोवंश की संख्या 5.42 लाख तथा क्रासबीड की संख्या 2.56 लाख है।उन्होंने कहा कि गोकुल ग्राम योजना के तहत देशी गोवंश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन गायों का दुध व गोमूत्र को गुणवत्ता सबसे अच्छी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी गाय (बद्री गाय) की संख्या जरूर कम है लकिन इसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी है। इस नश्ल की गायों के संवर्धन के लिये चमावत में बद्री गो संवर्धन केन्द्र स्थापित किया गया है। यहां पर इनकी नश्ल सुधार एवं गुणवत्ता के विकास पर ध्यान दिया जा है वहां पर इस समय 150 गायें है इनकी संख्या बढाने के प्रयास किये जाने पर भी उन्होंने बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा प्रगतिशील पशुपालकों के हित में संचालित योजनाओं के माध्यम से भेड़ बकरी पालकों को अच्छी नस्ल तथा उच्च वंशावली के नरों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इंटरवेंशन से भेड़ बकरी पालकों के पशुधन में सुधार होगा तथा ऊन व मांस के अधिक उत्पादन से उनकी आय में गुणात्मक वृद्धि होगी।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निर्धारित अवधि से पूर्व इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारम्भ होना बेहतर कार्य संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसान व पशुपालकों को पहुंचे इसके लिए प्रभावी प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गाय को गौ माता का सम्मान देने के लिए उत्तराखंड द्वारा प्रभावी पहल की गई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों, पशुपालकों के व्यापक हित में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पशुपालकों व मत्स्यपालकों को भी किसान का दर्जा दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी इन्हें प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दूध वितरण की व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया है।

इस अवसर पर सचिव पशुपालन श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि पशुपालन विभाग पशुपालकों के कल्याण हुतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड सेक्स सार्टड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित करने की तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा कालसी स्थित भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के तहत उक्त प्रयोगशाला को राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु रुपये 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी तथा साथ–साथ उक्त स्थान पर इसके साथ प्रशिक्षुओं हेतु अत्याधुनिक हॉस्टल का भी निर्माण रुपए 4.63 करोड़ की लागत से किया जाएगा इस केंद्र पर समस्त देश के पशु चिकित्सावदों तथा वैज्ञानिकों को भ्रुण प्रत्यारोपण तकनीक का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उच्च नस्ल की वंशावली के पशुओं में वृद्धि की जाएगी तथा प्रदेश एवं सम्पूर्ण राष्ट्र के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।

उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा रुपए 10.33 करोड़ की लागत से पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश में क्रॉस ब्रीड हीफर रियरिग फार्म की स्थापना की जाएगी उक्त योजना के तहत उत्तराखंड के पशुपालकों को उन्नत नस्ल की बछियां तैयार कर उपलब्ध कराई जाएंगी योजना के संचालन से प्रदेश के पशुपालकों के अवर्गीकृत उत्पादन करने वाले पशुओं को रिप्लेस किया जाएगा जिससे उनके germpool में योगदान से राज्य के पशुधन में अनुवांशिक सुधार हो सकेगा।

इस अवसर पर मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनीता ममगाई, इगुरान सोर्टिंग टेक्नालाजी के श्री प्रकाश कालेकर, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री विनोद आर्य, निदेशक पशुपालन डा. के.के.जोशी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(03/42)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य हित में प्रदेश के अनेक महानुभवों को विभागीय दायित्व सौंपे हैं। जिन महानुभावों को कैबिनेट मंत्री स्तर प्रदान किया गया है उनमें बलराज पासी को उपाध्यक्ष प्रथम राज्य स्तरीय जलागम परिषद, ज्योति प्रसाद गैरोला को उपाध्यक्ष द्वितीय राज्य स्तरीय जलागम परिषद का दायित्व प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिन महानुभावों को राज्य मंत्री स्तर प्रदान किया गया है उनमें जितेंद्र रावत मोनी को उपाध्यक्ष राज्य युवा कल्याण परिषद, डा. कल्पना सैनी उपाध्यक्ष अन्य पिछड़ा आयोग, लेफ्टि. (अ.प्र.) केडी भोटिया अध्यक्ष गोरखा कल्याण परिषद, कर्नल (अ.प्र.) सीएम नौटियाल उपाध्यक्ष राज्य सैनिक कल्याण परिषद, आचार्य शिव प्रसाद मंमगाई उपाध्यक्ष चार धाम विकास परिषद, अब्बल सिंह बिष्ट उपाध्यक्ष भागीरथी घाटी विकास परिषद, रामकृष्ण रावत उपाध्यक्ष उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद, मूरत राम शर्मा उपाध्यक्ष उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद, एसपी चमोली उपाध्यक्ष अर्ध सैनिक कल्याण परिषद, भगत राम कोठारी अध्यक्ष गन्ना एव चीनी विकास उद्योग बोर्ड, रविंद्र कटारिया–उपाध्यक्ष द्वितीय पशु कल्याण बोर्ड, अमी चंद बाल्मीकि अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, अजय राजौर उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, मजहर नईम नवाब उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, कृष्ण कुमार सिंघल उपाध्यक्ष जीएमवीएन, रेनू अधिकारी उपाध्यक्ष केएमवीएन, अशोक खत्री को उपाध्यक्ष श्री बदरी नाथ केदारनाथ मंदिर समिति का दायित्व सौंपा गया है।

इसके साथ ही जिन महानुभावों को विभिन्न आयोगों एवं समितियों में सदस्य नामित किया गया है उनमें प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अम्बानी के पुत्र अनंत अंबानी को श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति में इंद्रमणी गैरोला, श्रीमति चंद्र कला ध्यानी, अनिल कंसल, रामसूरत नौटियाल, ऋषि सती, अरुण मैठाणी, धीरज पंचभैया मोनू, राजपाल सिंह पुंडीर को भी सदस्य के रूप में, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के अन्तर्गत असगर अली, राव कालेखां, अब्दुल हफीज, हेमंत जोजफ, मास्टर शकील, संतोष नागपाल, तसलीम व गुलाम मुस्तफा, सफाई आयोग के सदस्य में जयपाल बाल्मीकि, साकेत बाल्मीकि, विपिन चंचल, एवं विनोद कुमार, निदेशक मंडल सदस्य जीएमवीएन में लोकेंद्र सिंह बिष्ट, अंजली खंडेलवाल, आशुतोष वर्मा, चंद्रप्रकाश, राजेश कुमार, रोहित एवं पुष्पा बड़थ्वाल तथा निदेशक मंडल सदस्य केएमवीएन में कमल जिंदल, तारादत्त पांडेय, कुंदन बिष्ट, व राम सिंह कोरंगा को नामित किया गया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

बागेश्वर/देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(03/41)

मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में किया 253 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

ऊन कतरन योजना का भी शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में कुल 253.30 करोड़ की 115 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिसमें 69.58 करोड़ रूपये की 27 योजनाओं का लोकार्पण व 183.72 करोड़ रूपये की 88 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में मशीन द्वारा ऊन कतरन योजना का भी शुभारम्भ भी किया, जिसके द्वारा मशीन से ऊन के कतरन का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने मशीन द्वारा उन कतरन योजना हेतु 15.65 लाख की धनराशि की लागत से निर्मित इस योजना की घोषणा पिछले वर्ष की थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनायें चलाई जा रही बागेश्वर में बागनाथ धाम का जीर्णोधार, सड़कों का निर्माण, गरूड़ में फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में चीड़ की पत्तियों से रोजगार की अपार संभावनायें हैं। चीड़ की पत्तियों से बिजली बनाई जा सकती है। इसके तहत अभी तक 50 करोड़ रूपये के ठेके हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीड़ की पत्ती से बिजली निर्माण के क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जिससे बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा पहाड़ों से हो रहे पलायन को भी रोका जा सकेगा। राज्य सरकार पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कार्य कर रही है तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य भी किया जा रहा है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों का विकास हो सके। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी व्यवसायिक प्रवृति व विवेक से कार्य करे इसके लिए प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन दिये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत रूप में कृषि, सहकारिता, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, फूड पैकेजिंग कार्य के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है तथा समूहों के लिए 05 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारम्भ किये जाने से असंगठित कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में मजदूरों की लगभग 92 प्रतिशत संख्या असंगठित कामगार है। इस योजना के लिए वे पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है तथा उनकी महीने की आमदनी 15 हजार से कम हो। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु के लाभार्थी जिसका श्रम विभाग में पंजीकरण हो वे एक नियत धनराशि प्रतिमाह जमा करायेंगे इस नियत धनराशि के बराबर ही धनराशि सरकार द्वारा जमा करायी जायेगी। लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पेंशन का पात्र होगा। इस योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी की बीच में दुर्घटनावस मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 06 लाख रूपये की धनराशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 05 लाख 37 हजार लोगों के कार्ड बनाये गये। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से प्रदेश के सभी परिवारों को जोड़ा गया है। इस योजना में सभी पात्र व्यक्तियों का 05 लाख तक के निःशुल्क ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधामंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 75 हजार लाख के बजट का प्राविधान किया गया है, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कपकोट क्षेत्र के कई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। जिसमें दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मुनार बैण्ड की स्वीकृति, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी दान सिंह भौर्याल की स्मृति में दियाली कुरोली में स्मारक निर्माण की स्वीकृति, बदियाकोट बनलेख डिग्री कॉलेज अंसों के पास मिनी स्टेडियम की स्वीकृति, खलीधार से चौड़ागॉव 02 किमी मोटरमार्ग का निर्माण, फल्यांटी चेटाबगड मोटरमार्ग रीठू भट्टी पुल से चेटाबगड होते हुए कनौली तक 06 किमी मोटर मार्ग के शासनादेश की स्वीकृति दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाई जा रही नन्दा गौरा देवी कन्या धन योजना के प्रारूप में बदलाव किया गया है जिसके तहत बालिका के जन्म के समय 11 हजार एवं इण्टर के उपरान्त 51 हजार की धनराशि दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में 05–05 हजार की किश्तों के रूप में धनराशि प्रदान की जाती थी।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत, विधायक श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, श्री चन्दन राम दास, जिला अध्यक्ष भाजपा शेर सिंह गढ़िया, जिला पंचायत सदस्य शिव सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू आदि उपस्थित थे।

नोट– जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(03/40)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने महिला दिवस पर सभी माताओं, बहनों व बेटियों को शुभकामनायें दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा है कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूज्यनीय एवं देवीतुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है कि देव शक्तियाँ वहीं पर निवास करती हैं जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज का युग परिवर्तन का युग है। आज नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उसने समाज व राष्ट्र को यह सिद्ध कर दिखाया है कि शक्ति अथवा क्षमता की दृष्टि से वह किसी से भी कम नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब नर–नारी, सभी के सम्मिलित प्रयास फलीभूत होंगे और हमारा देश विश्व के अन्य अग्रणी देशों में से एक होगा। तीलू रौतेली, रामी बौराणी, टिंचरी माई और गौरा देवी जैसी कई महान नारियों ने इस देवभूमि का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक वह नारी के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता। इसी भाव से मैं और मेरी सरकार अपनी देवभूमि की समस्त मातृ शक्ति के विकास के लिए पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता से निरन्तर प्रयासरत है। उनके बेहतर भविष्य के लिए हम सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रो में बहुत सारे सार्थक कदम उठा रहे है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किशोरियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रशिक्षण तथा पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना चलाई है। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ योजना के अन्तर्गत 63098 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए स्मार्ट फोन खरीदे जा रहे है, तथा राज्य में 19940 आंगनवाड़ी केन्द्रों के अलावा 350 अतिरिक्त नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा रहे है। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के अन्तर्गत 307 बेटियों को टैबलेट दिए गए है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए नंदाकृगौरा योजना चलाई जा रही है, इसके साथ–साथ नवजात बच्चियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनको वैष्णवी हेल्थ किट मुहैया करवाई जा रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए हरिद्वार में महिला छात्रावास तैयार हो गया है और देहरादून में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भारतीय सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए राज्याधीन सेंवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवायोजन का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए देवभोग प्रसाद योजना शुरू की गई थी जिसमें बद्रीनाथ के महिला समूहों ने सिर्फ एक वर्ष में डेढ करोड़ रूपये का प्रसाद बेचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से महिलाओं को एल०ई०डी० उपकरण बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम अपने प्रदेश की महिला समुहों को 5 लाख रूपये तक का कर्ज बिना ब्याज के मुहैया करवा रहे है ताकि वो अपना खुद का व्यापार शुरू कर सके। देहरादून और हल्द्वानी में हमने 2 महिला बैंक स्थापित किये जिनमें सभी कर्मचारी सिर्फ महिलाएं ही है। एकल महिलाओं के लिए हमने सखी ई–रिक्शा योजना भी चलाई है ताकि वो अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सके। इसके अलावा भी हमारी सरकार बालिकाओं व महिलाओं के पोषण एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(03/39)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से यमुनोत्री मार्ग के लिए हृदय रोग सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्डिएक मोबाईल यूनिट स्वच्छ आईकोनिक प्लेस के अंतर्गत गेल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा सीएसआर के तहत स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी उत्तरकाशी श्री आशीष चौहान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में यमुनोत्री के यात्रा मार्ग पर एक वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क आधारित सीसीटीवी और संचार प्रणाली की स्थापना के लिए गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 72 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2018–19 में जिला प्रशासन उत्तरकाशी के मार्गदर्शन में कुल 2 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

जिलाधिकारी श्री चौहान ने बताया कि बड़कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्डियक केयर आईसीयू का लोकार्पण किया गया है, यह स्थान जानकी चट्टी से लगभग 45 किमी पहले है। उन्होंने बताया कि आज लोकार्पित की गयी कार्डिएक केयर मोबाइल मेडिकल यूनिट यात्रा सीजन के दौरान जानकी चट्टी में तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्डियक केयर मोबाइल मेडिकल यूनिट में ट्रांसपोर्ट वेंटीलेटर ऑक्सीविंट लाइफ (Transport Ventilator Oxivent Life), बाईफेसिक डिफिब्रिलेटर विद ईसीजी (Biphasic Defibrillator with ECG) और मल्टी–चैनल मल्टीपैरा मॉनीटर (Multi-channel Multi Para Monitor) जैसे विशेष उपकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आगामी यात्रा सीजन के लिए यमुनोत्री के ट्रेक मार्ग को स्वच्छ रखने हेतु विभिन्न कार्य किये जाएंगे। इसमें यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग से प्लास्टिक कचरे का निपटान, डस्टबिन एवं खच्चरों के लिए गुनगुने पानी की व्यवस्था शामिल होगी।

इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, श्री केदार सिंह रावत, उत्तरकाशी डीएम श्री आशीष चौहान, गेल नार्थ जोन के सीजीएम श्री गौतम प्रसाद उपस्थित थे। गौरतलब है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गेल को सीएसआर में यमुनोत्री के विकास का जिम्मा सौंपा गया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–2(03/38)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि समाज व प्रदेश के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। वर्तमान में नारी हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। प्रदेश की बेटियों ने हर क्षेत्र में नाम रोशन किया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं शीर्ष स्थान पर न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बिना ब्याज के पांच लाख रूपये तक का लोन दिया जा रहा है। ग्रामीण आर्थिकी के विकास की सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पैनिक बटन व शी–बॉक्स (She-Box) की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें मिलकर पूरी इच्छा शक्ति से इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–1(03/37)

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना से 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को निशुल्क मिलेगा दूध

- **मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना का शुभारम्भ किया।**
- **सप्ताह में दो दिन 100–100 एमएल दूध दिया जाएगा।**
- **जिला सहकारी बैंकों के लिए सचल एटीएम व सहकारी संस्थाओं व पतंजलि आयुर्वेद के मध्य संयुक्त स्वदेशी उद्यम की भी शुरूआत की गई।**

जल्द ही प्रदेश के 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100–100 एमएल दूध निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। गुरूवार को परेड़ ग्राउन्ड, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया। डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि. व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रारम्भ की गई इस योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुगंधित मीठा स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना का विधिवत शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बच्चे स्वस्थ हों तो देश का भविष्य भी स्वस्थ व सुरक्षित रहेगा। बचपन में ही पोष्टिक आहर उपलब्ध हों तो पूरा जीवन शरीर व मन स्वस्थ रहता है। हमें अपने प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। इसमें सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाहर से अधिक दूध देने वाले पशु लाए जा सकते हैं। हमारी सरकार ने दुग्ध समूहों के क्षमता विस्तार के लिए 24 करोड़ रूपए व पशुपालकों को 8 हजार गायें अभी तक दी हैं। चारा यातायात अनुदान में 8 करोड़ रूपए दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बेटे–बेटी में भेदभाव को दूर करना होगा। यह तभी हो सकता है जबकि हमारी संकीर्ण मानसिकता दूर हो। भारतीय समाज में हमेशा बेटियों के विवाह के बारे में ही सोचा जाता है। जबकि उनकी पढ़ाई व कैरियर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार की एक योजना गौरादेवी कन्याधन योजना है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक कई चरणों में धनराशि का प्राविधान था। अब हमने विवाह के बजाय बेटी के इंटरमीडिएट करने पर ही पूरी धनराशि दिए जाने का प्रावधान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या भ्रुण हत्या एक अभिशाप है। इस बुराई को सामाजिक चेतना से दूर किया जा सकता है। अगर कहीं पर इस तरह का कृत्य पता चलता है तो सरकार को अवगत कराएं। सीएम हेल्पलाईन 1905 पर भी सूचित कर सकते हैं। सरकार सख्त एक्शन लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हम किसानों को एक लाख रूपए तक का ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर दे रहे थे। परंतु अब जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर विकास के रास्ते पर साथ लेकर चलें।

सहकारी मंत्री डा. धनसिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना एक बड़ी सौगात है। इसका आने वाले समय में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100–100 एमएल दूध निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। उत्तराखण्ड सरकार इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश में 18 हजार बच्चे कुपोषण क शिकार हैं। इनके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी बच्चे लाभान्वित होंगे। पोषण होगा तभी उत्तराखण्ड रोशन होगा।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के तत्वाधान में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित जिला सहकारी बैंकों के लिए सचल एटीएम का लोकार्पण व सहकारी संस्थाओं एवं पतंजलि आयुर्वेद लि. के मध्य संयुक्त स्वदेशी उद्यम का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को ब्याजमुक्त 5 लाख रूपए ऋण का चैक भी दिया। किसान क्रेडिट कार्ड के समान ही प्रारम्भ किए गए मत्स्य व पशुपालन कार्ड भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री दिलीप सिंह रावत, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री दान सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, अधिकारी, आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग